(v) FOOD-FOR-WORK PROGRAMME

श्री बी. डी. सिंह (फूलपूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एतद् द्वारा माननीय कृषि एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री का ध्यान "काम के बदले अनाज" योजना की ओर आकृष्ट चाहता हूं । व्यावहारिक दृष्टि से यह योजना इस समय पूर्ण रूप से रूक गई है । गत वर्ष भयंकर सूखे के समय यह कार्यक्रम कृषि श्रमिकों के लिए वरदान सिध्द हुई थी । इससे उन्हें रोजी-रोटी का सहारा मिल गया था और बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों एवं सड़कों का निर्माण भी हो गया था । इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर सरकार ने भी अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है, "इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जाना है तथा बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया जाना है, क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य में प्रमुख भूमिका अदा करने की क्षमता है। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केवल अनाज के रूप में ही नहीं, बल्कि नकदी सहायता भी दी जाएगी और बजट में इस कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है ।

परन्तु खेद है कि इस भयंकर मूल्यवृध्दि एवं आर्थिक थपेड़ों से त्रस्त गरीब श्रमिकों का जीवन आधार ही छीन लिया गया। भारतीय कृषि में दिसम्बर से फरवरी ऐसे महीने होते हैं, जब कृषि श्रमिकों को कोई काम नहीं मिलता। उन्हें अपनी भूख मिटाने तक का साधन नहीं उपलब्ध हो पाता। इन परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को हर संभव प्रयास करके चलाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार प्रांतीय सरकारों से तुरन्त वस्तुस्थिति की जानकारी करें और उन्हें इस कार्यक्रम को अबाधगति से चलाने के लिए आवश्यक खाद्यान्न एवं नकदी की व्यवस्था करें। अतएव सरकार का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि काम के बदले अनाज योजना को वह प्राथमिकता के आधार पर चलाती रहे। इसके अन्तर्गत सड़क एवं तालाब निर्माण, वृक्षारोपण, भूसंरक्षण, जलनिकास, सार्वजनिक भवन निर्माण आदि संबंधी कार्य सुविधा पूर्वक लिए जा सकते हैं।

इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितताओं की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा । पिछले 8-10 माह में इसमें बड़ी-बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। निसहाय गरीबी के मुंह की रोटी लूटनेवालों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक जनपद में एक जांच समिति का गठन होना चाहिए। जांच समिति में सभी दल के लोग एवं उपयुक्त अधिकारी हों और समिति एक निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे समिति यह भी सुझाव दे कि इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी ढंग से कैसे चलाया जाए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को यदि समुचित दण्ड नहीं मिलता, तो प्रभावकारी लोग एवं अधिकारी अनुचित लाभ उठाते रहेंगे और असहाय गरीब का सदैव इसी प्रकार शोषण होता रहेगा ।

(vi) RETRENCHED GOVERNMENT EMPLOYEES OF BEAS PROJECT.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan): Sir, about 1,600 employees belonging to 63 categories of Beas project have been continuously going on 24 hour chain hunger strike since 2-12-79 for one year. Now one meployee is on fast unto death since 2-12-80. All these days they were protesting against the wrong policies of the Ministry of Energy by which the directly recruited employees of Central Government and are working for the last 14 years are to be declared surplus, and ultimately retrenched, whereas employees of various State Governments, who are working on deputation on this project, are to be retained for operation and maintenance works. These employees demand that as Beas Construction Board, as well as the Bhakra Beas Management Board, both are instruments of the Government of India the 61,00 quasi permanent Central Government employees should have preferential right than the deputationiists to work on the posts of Base Project, when these posts are transferred along with Beas Construction Board to the Bhakra Beas Management Board.